सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

प्रेस विज्ञप्ति *रांची,दिनांक–15.5.2018*

- **मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्तहिक समीक्षा बैठक में 19 मामलों की हुई समीक्षा।**

मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव श्री रमाकांत सिंह ने कहा कि जमीन के एवज में मुआवजा देना तय समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें। श्री सिंह आज सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आई शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कुल 19 मामलों की समीक्षा की व आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये।

सरायकेला खरसावां में 1991 में जल संसाधन विभाग के द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और आज तक उनका मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जमीन के एवज में मिलने वाली विकास पुस्तिका के लिए भी रैयतों को उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा। इसी मामले की समीक्षा के दौरान श्री सिंह ने कहा कि जमीन अधिग्रहण किए हुये 27 साल से अधिक हो गया और अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसी परस्थिति में आखिर ग्रामीण आपको जमीन क्यों देंगे। उन्होंने किसी भी कीमत पर एक सप्ताह के अंदर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश संबन्धित विभाग को दिया।

साहेबगंज में पेयजलापूर्ति को लेकर सारे कार्य पूर्ण होने व पाइप लाइन बिछ जाने के बावजूद पानी नहीं मिलने की शिकायत को लेकर पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता ने बताया कि बिजली कनेक्शन में त्रुटि होने के कारण जलापूर्ति नहीं शुरू हो पायी है। इस मामले में संयुक्त सचिव ने कहा कि इतनी गर्मी के बावजूद आपलोग अभी तक पानी आपूर्ति शुरू नहीं कर पाये हैं। उन्होने तीन दिन के अंदर सारे विसंगतियों को दूर करते हुये पानी की आपूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया।

चतरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी शमशीर रजा की गिरफ्तारी नहीं होने की मामला भी समीक्षा में आया। इस मामले में डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तारी का प्रयास जारी है, अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है। मामले में एआईजी टु डीजीपी शम्स तबरेज ने डीएसपी को सीधा निर्देश दिया कि प्रयास की बात नहीं करें। आरोपी को गिरफ्तार

करें, यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई करें। इस निर्देश के बाद डीएसपी ने दो दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही।

जामताड़ा में चौकीदार दयामय बावरी की मौत के बाद उनकी पत्नी को नौकरी देने के मामले में जिले के नोडल अधिकारी ने बताया कि मृतक की पत्नी के द्वारा नौकरी के लिए जो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है वो पंजाब का है और संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसकी जांच के बाद ही उन्हें नियुक्ति दी जा सकती है। इसपर संयुक्त सचिव ने कहा कि मामले को बेवजह नहीं लटकाएँ। अविलंब जांच प्रक्रिया पूर्ण कर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुये रिपोर्ट भेजें।

कोडरमा के शिवम आयरन के द्वारा प्रदूषण के मापदंडो का उल्लंघन करते हुये काफी मात्रा में काला धुआँ उत्सर्जित किया जाता है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले में संयुक्त सचिव ने संबन्धित विभाग को अविलंब कार्रवाई करते हुये रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

दुमका के शिकारीपाड़ा में पर्यटन ,कला संस्कृति, खेलकुद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था जो 3 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। इस मामले में नोडल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस मामले में संबन्धित विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इस योजना की उपयोगिता से संबन्धित प्रतिवेदन जिला से मांगा गया है , उसके बाद ही पुनः राशि का आवंटन किया जा सकता है। संयुक्त सचिव ने दो दिनों के अंदर उपयोगिता से संबन्धित प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया ताकि इस आगे की कार्रवाई की जा सके।

खूंटी के गोहराम गाँव में ट्रांसफार्मर जलने के एक साल बाद भी नहीं बदले जाने की शिकायत आई। इस शिकायत के संबंध में संबन्धित जिला के अधिकारी ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए स्टिमेट तैयार कर लिया गया है। शीघ्र बादल दिया जाएगा। इसपर संयुक्त सचिव ने कहा कि ट्रांसफार्मर जलने में एक साल हो गया और अभी तक आप स्टिमेट ही बना रहे हैं। जले हुये ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए स्टिमेट की जरूरत ही क्या है ? एक सप्ताह के अंदर ट्रांसफार्मर बदलकर इसकी रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करिए।

धनबाद में सेवानिवृत पुलिसकर्मी की मौत के एक साल के बाद भी उनके परिजनों को पेंशन भुगतान शुरू नहीं होने के मामले में जिले के नोडल अधिकारी ने बताया कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही भुगतान आरंभ हो जाएगा। उन्होने कहा कि इस मामले में हुये विलंब को लेकर दोषी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। संयुक्त सचिव ने कहा कि सारी विसंगतियों को दूर करते हुये एक सप्ताह के अंदर पेंशन भुगतान आरंभ हो इसकी चिंता करें।

लोहरदगा के सुंदरू गाँव में सोलर प्लेट खराब होने के कारण दो साल से जलापूर्ति ठप्प है। इस वजह से ग्रामीणों को पेयजल की समस्या हो रही है। मामले को लेकर कार्यपालक अभियंता ने 14वें वित्त के मद से कार्य कराये जाने की बात कही। इसपर संयुक्त सचिव ने कहा कि दो वर्ष से ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं और आपलोग अभी तक विचार कर रहे हैं। उन्होंने 15 दिन के अंदर सोलर प्लेट की मरम्मत व अन्य विसंगतियों को दूर करते हुये पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

आज की समीक्षा के दौरान संयुक्त सचिव श्री सिंह ने जिलावार भी शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान शिकायतों के निष्पादन में शिथिलता बरतने व सबसे अधिक शिकायत लंबित रखने वाले गिरिडीह, पलामू, धनबाद, देवघर व पश्चिम सिंहभूम के नोडल अधिकारियों से सवाल भी किया। नोडल अधिकारियों ने कहा कि शिकायतों की संख्या अधिक आने के कारण ऐसा हो रहा है। संयुक्त सचिव ने जनसंवाद के मामलों को गंभीरता से लेते हुये प्राथमिकता के आधार पर इन्हें निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनसंवाद में आने वाली शिकायतों के निष्पादन के लिए अपने जिले के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा करें और मामलों का निष्पादन करें।